B-344
L-07
Social Justice

केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय

अति संवेदनशील वर्ग

- अति संवेदनशील वर्ग का अर्थ
- अति संवेदनशील वर्ग और सामाजिक न्याय
- भारत में प्रमुख अति संवेदनशील वर्ग
- अति संवेदनशील वर्ग की समस्याएं एवं कारण
- अति संवेदनशील वर्ग के सशक्तिकरण हेतु प्रयास
    - अति संवेदनशील वर्ग के सशक्तिकरण हेतु नीतिगत प्रयास
    - अति संवेदनशील वर्ग के सशक्तिकरण हेतु योजना एवं प्रयास
    - मूल्यांकन एवं सुझाव
    - समसामयिक मुद्दे

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

भारत में अति संवेदनशील वर्ग - अल्पसंख्यक

- अर्थ एवं स्वरूप
- भारतीय अल्पसंख्यकों की समस्याएं
- अल्पसंख्यकों के लिए किए गए संवैधानिक एवं वैधानिक रक्षोपाय
- अल्पसंख्यकों हेतु किए गए नीतिगत प्रयास एवं योजनागत प्रयास
- मूल्यांकन एवं सुझाव
- समसामयिक मुद्दे
  - (A) अल्पसंख्यकों की परिभाषा का मुद्दा
  - (B) अल्पसंख्यकों के आरक्षण का मुद्दा

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR
Scanned by CamScanner

भारत में प्रमुख अति संवेदनशील वर्ग

- अल्प संख्यक
- श्रमिक वर्ग
- अनुसूचित जाति
- गरीब एवं भूखे
- महिलाएं
- अनुसूचित जनजाति
- बच्चे
- वृद्ध
- मादक द्रव्य व्यसनी
- ट्रांसजेंडर
- घुमंतु जनजाति
- दिव्यांग

अल्पसंख्यक समुदाय की परिभाषा, अर्थ एवं स्वरूप :-

सामान्य अर्थों में वह समुदाय जिनकी संख्या कम हो, जो कुछ मामलों में वंचित हों, जो स्वयं को वंचित महसूस करते हों और जिनकी विशिष्ट भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक पहचान हो, जिसके आधार पर वे अपने को अलग महसूस करते हों, अल्पसंख्यक समुदाय कहे जाते हैं, परन्तु

भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं है और अनु० 29 में अल्पसंख्यक शब्द को शामिल किया गया है और कहा गया है कि " यह नागरिकों का वह हिस्सा है जिनकी भाषा लिपि अथवा संस्कृति भिन्न हो यह एक पूरा समुदाय हो सकता है जिसे सामान्य रूप से एक अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक समूह के रूप में देखा जाता है।

अनु० 30 में विशेषतौर पर अल्पसंख्यकों की दो श्रेणियों - धार्मिक एवं भाषाई का उल्लेख किया गया है।

अनु० 350 (A), (B) केवल भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित है

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अनुसार - अल्पसंख्यक वह समुदाय है जिसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम - 1992 की

KGS IAS
KHAN SIR
Scanned by CamScanner

धारा-2(c) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

⇓

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2(c) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 1993 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें 5 धार्मिक समुदाय- मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया और पुनः 27 जनवरी, 2014 को इसमें जैन को छठे अल्पसंख्यक समूह के रूप में शामिल किया गया।

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS KHAN SIR

अल्प संख्यक की परिभाषा संबंधी विवाद :-

1. अल्पसंख्यक की स्पष्ट परिभाषा दी जाए?
2. अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा का आधार राज्य हो या केन्द्र?
3. क्या हिन्दू धर्म को कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया जाना चाहिए?

Scanned by CamScanner

समीक्षा

निश्चित ही अल्पसंख्यक की परिभाषा की समस्या आज प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है, ऐसे में जरूरत है अल्पसंख्यक समुदाय की एक वस्तुनिष्ठ परिभाषा देने की, जो संविधान में निहित अनुदेशों के अनुरूप हो, इस हेतु यदि अल्पसंख्यक की परिभाषा का निर्धारण, राज्य स्तर पर किया जाये और इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषायी विशिष्टता के साथ-साथ, वंचितता के तत्वों को भी आवश्यक रूप से शामिल किया जाए तो तर्क संगत होगा।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

भारतीय अल्पसंख्यकों की समस्या / अति संवेदनशीलता का स्वरूप :-

मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या :-

1. गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या
2. अशिक्षा एवं रूढ़िवादिता की समस्या
3. स्त्रियों की निम्नतर स्थिति का होना
4. भय एवं असुरक्षा की समस्या
5. सांप्रदायिकता एवं जान-माल की हानि
6. जनसंख्या वृद्धि की समस्या

ईसाई अल्पसंख्यक की समस्या :-

1. धर्मांतरित ईसाईयों में गरीबी की समस्या।
2. धर्मांतरित दलित ईसाईयों में छुआछूत की समस्या।
3. हिंदू कट्टरतावाद के उभार से, ईसाईयों मे भय एवं असुरक्षा की समस्या।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform

Scanned by CamScanner

अल्पसंख्यकों हेतु किये गए संवैधानिक एवं वैधानिक रक्षोपाय :-

(i) सामान्य क्षेत्र एवं पृथक क्षेत्र की संकल्पना

⇓

पृथक् क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार

	अनुच्छेद	विशेषताएँ
A	29(1)	अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार
B	29(2)	धर्म/भाषा के आधार पर किसी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से रोके जाने पर पाबंदी।
C	30(1)	अपना शैक्षणिक संस्थान खोलने एवं प्रबंधन का अधिकार।
D	30(2)	अल्पसंख्यकों के प्रबंधन वाले शैक्षिक संस्थाओं को राज्य से प्राप्त सहायता में भेदभाव का निषेध
E	350	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

Scanned by CamScanner

(iii) संविधान में बहुलक समाज की प्रास्थिति को स्वीकार्यता अर्थात विविधता में एकता के आदर्शों को स्वीकृति।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय जिसका गठन 17 मई 1993 को पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में हुआ।

उद्देश्य / कार्य :-

1. अल्पसंख्यकों की उन्नति तथा विकास का मूल्यांकन करना।
2. इनके संरक्षण से जुड़े कार्यों की निगरानी करना।
3. इनके संरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्लान बनाना।
4. इनसे संबंधित शिकायतों को देखना और उनसे जुड़े अधिकारियों के समक्ष रखना।
5. इनके विकास से जुड़े अध्ययन, अनुसंधान तथा विश्लेषण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

Scanned by CamScanner

6. इनकी समस्याओं एवं कारणों के समाधान के उपायों की अनुशंसा करना आदि।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग : समीक्षा

निश्चित ही, यह आयोग अल्पसंख्यकों के विकास एवं रक्षोपाय में सहायक रहा है, परन्तु इनकी अनुशंसाओं को दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ लागू करके ही, अल्पसंख्यकों के रक्षोपाय में इस आयोग को प्रासंगिक बनाया जा सकता है।

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

Scanned by CamScanner

वक्फ प्रशासन एवं केन्द्रीय वक्फ परिषद

- मुस्लिमों या अल्पसंख्यकों की सार्वजनिक संपत्ति (वक्फ) की देखभाल या प्रशासन से संबंधित।
- 1964 में, भारत सरकार द्वारा, वक्फ अधिनियम 1954 द्वारा स्थापित।
- 1995 में वक्फ प्रशासन अधिनियम पारित और 2013 में संशोधन।
- इसके द्वारा वक्फ परिषद को अत्याधिक अधिकार प्रदान किये गए।
- इसके द्वारा एक केन्द्रीय वक्फ परिषद का गठन
- यह परिषद वक्फ के समुचित प्रशासन, विकास एवं प्रबंधन से जुड़े कार्यों का निष्पादन करती है।
- 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश - बिना किसी चर्चा के इसे JPC (संयुक्त संसदीय समिति) को भेजा गया।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग

किसी भी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा देने और उसे देश के किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियम 2004 पारित करके इस आयोग का गठन किया गया।

(पुनः 2006 और 2010 में इसमें संशोधन किया गया।)

2010 के संशोधन के बाद राज्य सरकारों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को आवेदन पत्र मिलने के 60 दिनों के भीतर NOC देना होगा, नहीं देने पर आयोग सुनवाई कर सकता है और जरूरत पड़ने पर स्वयं ही NOC प्रदान कर सकता है।

संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयासों की समीक्षा एवं सुझाव :-

निश्चित रूप से उपरोक्त संवैधानिक एवं वैधानिक रक्षोपायों ने अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है; जैसे...
(उपलब्धियों की चर्चा करें)

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

Scanned by CamScanner

B. बावजूद इसके हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं और भारतीय अल्पसंख्यकों से, मुख्यतः मुस्लिमों से जुड़ी कई समस्याएँ आज भी बनी हुई हैं। (कमियों एवं समस्याओं की चर्चा करें तथा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा करें)

C. इस स्थिति के लिए मुख्यतः निम्न कारण उत्तरदायी रहे हैं:-

1. संविधान एवं कानून की अस्पष्टता
2. जटिल लेट-लतीफ एवं महंगी न्याय व्यवस्था
3. मुख्यतः मुस्लिमों में अशिक्षा एवं जागरूकता की कमी।
4. सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार
5. धर्म का राजनीतिकरण
6. कानून प्रवर्तन एजेन्सियों में दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव तथा भ्रष्टाचार

D- इसलिए उपरोक्त कमियों एवं बाधाओं को दूर करके ही अल्पसंख्यकों को मिले संवैधानिक एवं वैधानिक रक्षोपायों को सार्थक बनाया जा सकता है।
(उपरोक्त कारणों के सन्दर्भ में सुझावों की चर्चा करें)

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform

Scanned by CamScanner